वर्ष 9 अंक 12 दिसम्बर 1987 दो रुपये

# सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

**सीटू वर्किंग कमेटी मीटिंग**

**चंडीगढ़, दिसम्बर 1-3, 1987**

## अध्यक्षीय भाषण

**बी. टी. रणदिवे**

कामरेडों,

सबसे पहले तो हमें उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए' जिन्होंने पंजाब में अपनी मातृभूमि की एकता की रक्षा के लिए लड़ते हुए प्राणों की आहुति दी है. पिछले कोई तीन साल या उससे भी ज्यादा अर्से से पंजाब, भारतीय एकता तथा स्वतंत्रता के रक्षकों और उसे तोड़ने वालों के बीच युद्ध क्षेत्र बना हुआ है.

सीटू, सी पी आइ (एम), डी वाइ एफ आइ, एटक तथा सी पी आइ के अनेक बहादुर कामरेड राष्ट्रविरोधी हत्यारों की गोलियों का निशाना बने हैं. उनमें ऐसे लोग भी थे, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से मैं जानता था. मैं सी पी आइ (एम) राज्य कमेटी सदस्य तथा पंजाब की जनता के बुजुर्ग नेता, कामरेड चन्नण सिंह धूत की याद को सलाम करता हू. मैं, कामरेड दर्शन सिंह की याद में सिर झुकाता हूं. जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता था. मैं भारत की जनवादी सभा के युवा नेता, दीपक धवन की याद को और दूसरे ऐसे सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो हिंदू-सिख एकता की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ते हुएश हीद हुए है. मैं, पृथकतावादियों की गोलियों से मारे गए दूसरे सारे लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं भले ही उनकी राजनीतिक संबद्धता कुछ भी क्यों न रही हो. और हमें, पुलिस के उन जवानों और अफसरों को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने आतंकवाद के खतरे से जुझते हुए अपने प्राण दिये हैं, ताकि विघटन के इस स्रोत को खत्म किया जा सके.

कामरेडों, आप सभी जानते हैं कि हमारे बहुत ही प्रिय कामरेड, नृसिंह चक्रवर्ती के दुखद तथा असामयिक निधन से सीटू को बड़ा भारी धक्का लगा है. वह कई सालों से, बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे संगठन के सचिव पद की जिम्मेदारी संभालते आ रहे थे. पिछले कुछ वर्षों में उनके साथ काम करते हुए मुझे अपनी आंखों से यह देखने का मौका मिला कि यह भूतपूर्व रेलवे मजदूर किस धातु का बना हुआ था. वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली, बड़ी व्यापक समझ-बूझवाले, बहुत ही अनुशासित व्यक्ति थे और एक दिन में दस आदमियों का काम करने में सक्षम थे. अपने आंदोलन की गहरी समझ, अनुशासन तथा समर्पण का ऐसा योग विरल लोगों में ही देखने को मिलता है, उनके निधन से सीटू को बड़ा भारी धक्का लगा है. देश के रेलवे आंदोलन को भी भारी धक्का लगा है.

### अक्तूबर क्रांति की सत्तरहवीं सालगिरह

कामरेडों, महान अक्टूबर क्रांति की सत्तरहवीं सालगिरह मनाने के एक महीने बाद हमारी बैठक हो रही है. इस महान युग प्रवर्तनकारी घटना ने एक के बाद एक, अनेक परिवर्तनों को प्रेरित करके विश्व इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है. सत्तरहवीं सालगिरह के मौके पर सोवियत मजदूर वर्ग तथा जनता ने और भी तीव्रतर प्रगति, जनता के बीच और ज्यादा खुशहाली के वितरण और समाजवादी निर्माण की गतिविधियों में सभी की और पूर्णतर हिस्सेदारी का एक नया दौर शुरू करने का फैसला लिया है. उस समय, जब पूंजीवादी दुनियां को झटके पर झटके लग रहे हैं, तिव्रत्तर विकास की पंद्रह वर्षीय योजना का लागू किया जाना, समाजवादी व्यवस्था की श्रेष्ठता को एक वार फिर सार्वित करता है. सीटू, आर्थिक उपलब्धियों तथा समाजवादी जनतंत्र के प्रसार में सोवियत मजदूर वर्ग तथा जनता की और ज्यादा कामयाबियों की कामना करती है.

अक्टूबर क्रांति के बाद के सत्तर सालों ने यह भी दिखाया

# 9 दिसम्बर को संसद चलो

है कि समाजवादी व्यवस्था विश्व शांति की रक्षा करने के लिए तथा युद्ध के खिलाफ, अनवरत संघर्ष करनेवाली ताकत है. वह सभी राष्ट्रों के बीच समानता तथा स्वतंत्रता, युद्ध तथा दूसरों के भूभाग हड़पने तथा दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने के विरोध और बात चीत के जरिये अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे पर आधारित विदेश नीति पर चलती है. यह नीति, मार्क्स की सर्वहारा अंतर्राष्ट्रवाद की शिक्षाओं का परिणाम है, जिसे लेनिन ने, अपनी शांति की आज्ञप्ति के जरिए, आगे बढ़ाया. सीटू तथा भारत का मजदूर वर्ग, विश्वशांति की रक्षा के लिए सोवियत संघ के इस अथक प्रयास की सराहना करता है. सीटू आशा करती है कि अमरीकी साम्राज्यवादियों को अकल आयेगी और मध्यम मार क्षमता की मिसाइलों के सम्बन्ध में बातचीत के सफलता के साथ पूरे होने की राह की सारी बाधाएं दूर होंगी. सीटू यूनियनों को, विश्व शांति के लक्ष्य के लिए संघर्ष करने और नाभिकीय युद्ध को टालने तथा मानव जाति को सर्वनाश से बचाने के सोवियत प्रयासों को मजबूत बनाने के लिए शपथ लेनी चाहिए.

## बंगला देश और श्रीलंका की स्थिति

कामरेडों, सीटू को बंगला देश के मजदूर वर्ग तथा जुझारू अवाम को हार्दिक शुभकामनाएं देनी चाहिए, जो जनरल इरशाद के फौजी तानाशाह निजाम के खिलाफ एक न्यायसंगत संघर्ष चला रहे हैं. फौजी हुकूमत ने भयंकर दमन शुरू कर दिया है, कम्युनिस्ट पार्टी को गैरकानूनी घोषित कर दिया है और वर्तमान आंदोलन की दो महिला नेताओं — शेख हसीना तथा बेगम खालिदा — को गिरफ्तार कर लिया है.

सीटू को यकीन है कि बंगला देश का मजदूर वर्ग, इस संघर्ष में अपनी ऐतिहासिक भूमिका अदा करेगा और जनतांत्रिक ताकतों को, फौजी निजाम से मुक्ति पाने और एक लोकप्रिय सरकार के लिए रास्ता बनाने में समर्थ बनायेगा. सीटू, जनतंत्र के योद्धाओं की हत्याओं की कड़ी निंदा करती है और इस फौजी अतंकवाद के शिकार हुए लोगों के प्रति अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार करती है.

कामरेडों, श्रीलंका की घटनाएं जनता के लिए चिंता का कारण बनी हुई हैं, जो स्वाभाविक ही है. भारत की शांति रक्षक सेनाएं, जो दमन से तमिलों की रक्षा करने के लिए और उनकी न्यायोचित मांगें पूरी कराने के लिए भेजी गयी थीं, अब तमिलों के ही एक लड़ाकू संगठन, लिट्टे का सामना कर रही हैं. कुछ हलकों से यह मांग उठ रही है कि भारतीय शांति रक्षक सेना को फौरन वापस बुला लेना चाहिए. ये लोग, इस बात की ओर से अपनी आंखें ही बंद किये हुए हैं कि श्रीलंका में साम्राज्यवाद का क्या खेल चल रहा है. भारत तथा श्रीलंका के जातीय टकराव का हल निकालने की जो कोशिश की गयी है, वह साम्राज्यवादियों को कभी पसंद नहीं आयी, हालांकि उन्होंने उसका समर्थन करने का ढ़ोंग जरूर किया है. दरअसल, इस समझौते पर दस्तखत होने से, इस विवाद के निपटारे की पहल दोनों सरकारों के हाथों में आ जाती है और बाहरी हस्तक्षेप के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती है. अगर इस समझौते को पूरी तरह लागू किया जाता, तो दो गुटनिरपेक्ष देशों के बीच मैत्री की बड़ी भारी जीत होती और हस्तक्षेपकारियों की, साम्राज्यवाद की अस्थिरताकारी ताकतों की हार होती. लिट्टे हो या सिंहली कट्टरपंथी हों, वे सारे लोग जो समझौते के खिलाफ लड़ रहे हैं तथा उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, वस्तुगत रूप से श्रीलंका में साम्राज्यवादी हस्तक्षेप के ही हित में काम कर रहे हैं. अगर लिट्टे, अपने बचन से नहीं मुकरा होता और उसने इस समझौते का त्याग नहीं किया होता, जिसे उसने निष्ठापूर्वक स्वीकार किया था, तो यह दुखद स्थिति पैदा ही नहीं हुई होती. इसमें कोई शक नहीं कि लिट्टे के नेता संदेहों तथा विदेशी ताकतों की चाल के शिकार हो गये हैं और भारत के खिलाफ वही आरोप दुहरा रहे हैं, जो श्रीलंका में खुले तौर पर अमरीकापरस्त समझे जाने वाले हलकों द्वारा लगाये जा रहे हैं, जिनका नेतृत्व श्रीलंका का प्रधानमंत्री करता है. भारतीय शांति रक्षक सेनाओं को वापस बुलाने का एक ही मतलब हो सकता है—हस्तक्षेपकारी भाड़े के हत्यारों द्वारा, जिन्हें स्थिति से निपटने के लिए बुलाया जायगा, तमिल नागरिकों के नरसंहार की खुली छूट. स्थिति यह है कि भारतीय शांति रक्षक सेना, नागरिकों की जिंदगी तथा हिफाजत का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखते हुए स्थिति से निपटती रही है. फिर भी, यह समझना जरूरी है कि यह बहुत ही दुखद स्थिति है कि शांति रक्षक सेना को लिट्टे के खिलाफ अपने हथियरों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. और भारतीय शांति रक्षक सेना अगर, शांति रक्षा की अपनी कार्रवाइयों के दौरान, असैनिक तमिल आबादी की लगातार बढ़ती सहानुभूति नहीं जीत पाती है, अगर वह लगातार बढ़ते लोकप्रिय जनमत को अपने पक्ष में नहीं कर पाती है, तो उसका मिशन नाकाम रहा समझना चाहिए और उस स्थिति में उसे वापस बुलाना ही होगा. यह दोनों देशों की जनता के लिए जबर्दस्त राजनीतिक तथा कूटनीतिक हार होगी और हस्तक्षेपकारियों तथा उनके सहयोगियों की जबर्दस्त जीत होगी.

## पूंजीवादी दुनिया का संकट

कामरेडों, हमारे देश की आर्थिक स्थिति, जो पहले ही जनता के लिए बहुत तकलीफदेह तकलीफों तथा कठिनाइयों का कारण बनी हुई थी, अब पूंजीवादी दुनिया की अनिश्चितता को देखते हुए, अचानक और ज्यादा बिगड़ सकती है. हमारे देश की जनता को भारी अनिश्चितताओं का समना करना पड़ रहा है और देश के मजदूर वर्ग को, जिसे पहले ही छंटनी, तालाबंदियों तथा बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है, निकट भविष्य में और भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

ऐसा लगता है कि पूंजीवादी दुनियां में 1929 की कहानी दुहराई जा रही है. जब बढ़ती खुशहाली के आसार के बीच उसे अचानक, अपने इतिहास की सबसे भयंकर मंदी का सामना करना पड़ा था. 1929 के संकट के फूटने से ऐन पहले, अमरीकी राष्ट्रपति सारी दुनिया को यकीन दिला रहा था कि अमरीका अथाह खुशहाली के दौर में प्रवेश कर रहा है. अनेक वर्षों के बाद एक बार फिर वही कहानी दुहराई गई है. इस साल अक्टूबर में अमरीकी अर्थव्यवस्था ने लगातार प्रयास के अपने 59वें महीने में प्रवेश किया था और पिछले सारे रिकार्ड तोड़ दिये थे. कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे इतने नजदीक खाई है ! बेकारी की दर घटकर 5.9 फीसद रह गई थी, जोकि 1970 के बाद सबसे कम बेकारी को दिखाता है, आगे भी आर्थिक प्रगति के आसार दिखाई दे रहे थे. लेकिन तभी, अचानक स्टाक बाजार में धमका हुआ, जिसके धक्के से समूची पूंजीवादी दुनियां हिल उठी. इसके चलते भारी नुकसान हुए हैं और पूंजीवादी व्यवस्था की कमजोरी जगजाहिर हो गई है. स्टाक बाजारो में अफरा-तफरी का आलम है और इस पर गंभीरता से बहस की जा रही है कि स्टाक बाजार का संकट, एक और जबर्दस्त मंदी का पूर्वसंकेत है या नहीं. बड़ी जल्दी में कदम उठाये जा रहे हैं. लेकिन उनसे यह गिरावट रूकती दिखाई नहीं देती है.

अर्थशास्त्री, अमरीकी बजट घाटों को, ब्याज की बढ़ी हुई दरों को, डालर की कीमत में गिरावट की ओर अमरीका द्वारा सुनियोजित ढंग से लागू की जा रही नीति को, मौजूदा अनिश्चितताओं के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. लेकिन ऐसी समझ, बुनियादी कारणों तक तो पहुंचती ही नहीं है. और, ये बुनियादी कारण हैं: विकसित पूंजीवादी देशों की सरकारों पर इजारेदारियों का प्रभुत्व; राज्य-इजारेदार पूंजीवाद का उदय, जिसके अंतर्गत राज, इजारेदारों की हिफाजत के लिए अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करता है; खासकर अमरीका में सैन्य-औद्योगिक गठजोड़ का उदय, जो अपने क्षुद्र हितों के लिए सैनिक कार्यों तथा विनाशकारी हथियारों पर भारी खर्चों की मांग करता है; बहुराष्ट्रीय निगमों की बढ़ी हुई ताकत, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में अराजकता का एक और तत्व जोड़ते हैं; एक तिहाई दुनिया के समाजवाद का रास्ता अपनाने तथा इस प्रकार साम्राज्यवादी शोषण के जाल से बाहर निकल जाने के चलते मंदी के संकट का तीखा होना; पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था के पराभव के चलते, पिछड़े देशों की उनकी बेरोक-टोक लूट पर अंकुश लगाना, हालांकि इनमें से कई देश ऋण के फंदों में फंस गये हैं. यह संकट, पूंजीवादी देशों में उत्पादक शक्तियों के असमान विकास के चलते और बढ़ गया है और दूसरे विश्व-युद्ध की विजेता शक्तियों, अमरीका तथा ब्रिटेन, के मुकाबले विजित शक्तियां, जापान तथा जर्मनी, कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं. यह कल्पना कर पाना भी मुश्किल है कि पूंजीवादी व्यवस्था, अपने मौजूदा संकट से आसानी से निकल सकती है. और, पूंजीवादी पश्चिम में होनेवाली हर उथल-पुथल का, भारत पर असर पड़ना अवश्यंभावी है.

## भारत में बढ़ता आर्थिक संकट

हमारे देश के विशाल हिस्सों के सूखे तथा बाढ़ की गिरफ्त में होने के कारण, स्थिति और भी बिगड़ गयी है. कृषि-उत्पादन में जो भारी क्षति हुई है, उसका औद्योगिक-उत्पादन पर भी अवश्य प्रभाव पड़ेगा. देहाती इलाकों में क्रयशक्ति की गिरावट का, औद्योगिक मालों की मांग पर असर जरूर पड़ेगा और इससे अर्थव्यवस्था का संकट और बढ़ेगा. विश्वबैंक के अनुमान पहले ही कह चुके हैं कि इस साल सकल राष्ट्रीय उत्पाद की विकास दर शून्य रहने जा रही है और भुगतान संतुलन घाटा, पहले के मुकाबले एक अरब डालर ज्यादा रहने जा रहा है. और भारत को, एकबार फिर इस विश्व एजेंसी की "प्राण रक्षा" कार्रवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है. 30 करोड़ डालर के अतिरिक्त ऋण की पेशकश की गयी है, ताकि विश्व बैंक ने जिस 'सामान्य विकास' का नुस्खा पेश किया है, उसके अमल में बाधा न पड़े. अब, यह तो कौन बता सकता है कि इस "दयालुतापूर्ण काम" के बदले में क्या-क्या भारी शर्तें लगायी जायेंगी! बहरहाल, जो भी हो, विश्व बैंक पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 'करणीयों और अकरणीयों' का व्यापक ढ़ांचा तो तय कर ही चुका है और राजीव सरकार की नीतियां उसका पूरी तरह अनुसरण भी कर रही हैं.

विश्व बैंक, भारत सरकार पर जिस दिशा में जाने के लिए दबाव डाल रहा है, यह 1987 की विश्व विकास रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है: "लाइसेंसिंग प्रणाली ने, घरेलू उद्योग के बीच प्रतियोगिता को बाधित किया है और इसने प्रस्ताव ठुकराये जाने की ऊंची दर, लंबे-लंबे विलम्बों तथा उप-विभागीय प्राथमिकताओं में बदलाव को जन्म दिया है, जिससे यह (प्रणाली) विकास तथा (उद्योगों में) प्रवेश के लिए खासी बड़ी बाधा बन गयी है." यह, इस मांग के सिवा और कुछ नहीं है कि अर्थव्यवस्था पर ही नियंत्रण पूरी तरह हटा लिया जाय और इजारेदारों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों को इसके लिए खुली छूट दी जाय कि दूसरों के साथ प्रतियोगिता कर सकें तथा उन्हें तबाह कर सकें.

## आर्थिक उदारता की नीतियों ने संकट बढ़ाया

हाल ही में प्रेस ने खबर दी है कि विश्व बैंक की इन बेतहाशा मांगों को पूरा करने के लिए राजीव सरकार ने पूरा का पूरा खाका तैयार भी कर लिया था. ऐसा समझा जाता है कि लाइसेंसिंग प्रणाली का खात्मा करने, इजारेदार घरानों पर नियंत्रणों में छूट देने, विदेशी निवेश तथा तकनीकी आयातों को और ज्यादा बढ़ावा देने जैसी रियायतें मांगी जा रही थीं. प्रस्तावित ढ़ील के बाद, सिर्फ 2-3 सौ बड़ी कंपनियों पर, और

वह भी कुछ समय के लिए ही, थोड़ा-बहुत नियंत्रण रह जाना था.

बहरहाल, ऐसा समझा जाता है कि बोफोर्स घोटाले के भंडाफोड़ के बाद पैदा हुए राजनीतिक हालात को देखते हुए सरकार को, इन नयी रियायतों की घोषणा स्थगित करनी पड़ी.

बहर हाल, पिछले दो साल से इस नीति के पालन के बावजूद, अर्थव्यवस्था को उदार बनाने, उद्योग पर कम कर लगाने, घोषित कालाबाजारियों तथा चोरी-छिपे तस्करी के जरिए दूसरे देशों में विदेशी मुद्रा जमा करनेवालों को बढ़ावा देने की इन नीतियों के बावजूद, संकट ग्रस्त अर्थव्यवस्था को कोई राहत तो मिली नहीं है, यहां तक कि योजना लक्ष्य तक पूरे कर पाना कठिन बना रहा है. रिजर्व बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 1986-87 के बीच, विनिर्माण उद्योग के क्षेत्र में विकास की दर घटकर 7.2 फीसद रह गई, जबकि उससे पहले के साल में यही दर 10.6 फीसद थी. विनिर्माण के क्षेत्र में भी इंजीनियरिंग उद्योगों से सम्बन्धित आंकड़े दिखाते हैं — ये आंकड़े अक्टूबर तक के लिए ही उपलब्ध हैं — कि इस क्षेत्र में विकास की दर, इससे पहले के वर्ष की 12.2 फीसद दर के मुकाबले घटकर सिर्फ 6.7 फीसद, यानी आधी ही रह गई थी. दूसरी ओर, खदान व उत्खनन तथा बिजली-उत्पादन के क्षेत्रों में विकास दर अपेक्षाकृत ऊंची रही थी, फिर भी, सितम्बर 1986-87 में बुनियादी साधनों से सम्बन्धित छः उद्योगों की मिली-जुली विकास दर 7.4 फीसद रही, जबकि उससे पिछले साल में यही दर 7.9 फीसद थी. इसके अलावा, बुनियादी साधनों से सम्बन्धित सभी उद्योगों के लिए कुल मिलाकर 9.5 फीसद विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था, पूरा नहीं हो सका.

अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के सारे कदम बीमार उद्योगों को या छंटनीशुदा मजदूरों को कोई भी राहत दिलाने में विफल रहे हैं, रिजर्व बैंक आफ इंडिया की 1986-87 की रिपोर्ट बताती है: "छोटे, मंझले तथा बड़े उद्योगों में, औद्योगिक बीमारी बढ़ती जा रही है. यह बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि इसका असर समूची अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1986 के जून के महीने के आखिर तक बैंक द्वारा बीमार मानी गई इकाइयों की कुल संख्या बढ़कर 1,30,000 हो चुकी थी. इन इकाइयों पर बैंकों का 4,665 करोड़ रू. बकाया था, जो बैंकों के कुल ऋणों का 8.54 फीसद हिस्सा है और उद्योगों के (छोटे, मंझले तथा बड़े) के लिए बैंकों के कुल ऋण का 17 फीसद हिस्सा है.

और, जून 1986 के बाद से कितनी और इकाइयां बीमार हो चुकी हैं, इसका हिसाब तो फिलहाल कोई नहीं जानता है.

## जनता की बढ़ती बदहाली फूलते इजारेदार

यह तो स्वतः स्पष्ट है कि पूंजीपतियों को एक के बाद एक राहत देकर और दूसरी ओर बुनियादी अवाम को पामाल रखकर अर्थव्यवस्था के इस महारोग का इलाज नहीं किया जा सकता है.

इस नीति के परिणाम, जनता की बढ़ती बदहाली, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और दूसरी ओर इजारेदारों की परिसंपत्तियों में तेजी से बढ़ोतरी के रूप में देखे जा सकते हैं. बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ से भी ऊपर निकल गई है, जबकि देहाती इलाकों में करोड़ों लोगों को नियमित रोजगार नहीं मिलता है. लेकिन, इसके बावजूद, इजारेदारों के हाथों में संपत्ति तथा पूंजी का अधिकाधिक केंद्रीकरण रूका नहीं है. औद्योगिक विकास राज्यमंत्री ने पिछले दिनों ही लोकसभा में बताया कि वर्ष 1984 तथा 1985 के दौरान, बीस सबसे बड़े औद्योगिक घरानों की परिसंपत्तियां पिछले वर्षों के मुकाबले क्रमशः 18.7 फीसद तथा 29.5 फीसद बढ़ी थी. सबसे बड़े औद्योगिक घरानों की संपत्तियां 1983 में 13,103 करोड़ रू. के बराबर थीं, जो 1984 में बढ़कर 15,448 तथा 1985 में बढ़कर 20,136 करोड़ रू. तक पहुंच चुकी थीं. 1983-85 के बीच के दो सालों में, सबसे बड़े इजारेदार घरानों की परिसंपत्तियां 50 फीसद बढ़ गई. तब बिश्व बैंक तथा विदेशी बैंकों द्वारा, अर्थव्यवस्था के समझदारी पूर्ण संचालन के लिए भारत सरकार की तारीफ की जाती है, तो इस पर किसी को अचरज क्यों हो!

पांच सबसे बड़े औद्योगिक घरानों की परिसंपत्तियां इस प्रकार हैं: बिड़ला — 4,111 करोड़ रू. टाटा — 3,698 करोड़ रू. थापर (यह घराना हाल ही में सबसे बड़े घरानों की सूची में आया है) — 1,067 करोड़ रू. जे के सिंघानियां — 1,057 करोड़ रू; रिलायंस — 954 करोड़ रू.

सभी जानते हैं कि ये महानुभाव तस्करी के जरिये दूसरे देशों में विदेशी मुद्रा ले जाने का काम करते रहे हैं, विभिन्न तिकड़मों के जरिये, सैकड़ों करोड़ों रूपये की भारतीय विदेशी मुद्रा बाहर भेजी जा रही है. इनमें से एक बदमाश को जब पकड़ लिया गया और जुर्माना देने के लिए कहा गया, तो राजीव गांधी बौखला उठे. इस सबके चलते अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है, लम्बी-लम्बी मिलबंदियां तथा तालाबंदियां हो रही हैं, जबरियां रिटायरमेंट हो रहे हैं और लोगों के रोजगार छिन रहे हैं.

पश्चिम बंगाल से हाल में मिले आंकड़े दिखाते हैं कि 1987 के दौरान 56 में से 15 जूट मिलें बंद रही हैं. 19 जूट मिलों में तालाबंदी रही है. 1987 में 12 मिलों में तालाबदी थी और 7 में सालभर पहले से तालाबंदी चली आ रही थी. 39 कपड़ा मिलों में से 8 में तालाबंदी चल रही थी.

केन्द्र सरकार ने जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग ठुकरायी है, जबकि इस मांग को कांग्रेस (आइ) समेत प. बंगाल में सभी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन हासिल था. इसके

अलावा, हाल में घोषित कुछ कदमों के बावजूद, कृत्रिम रेशे से जूट के लिए उत्पन्न चुनौती को रोकने में सरकार विफल रही है. केन्द्र सरकार की नीतियों के चलते, जूट किसान तथा जूट मजदूर, दोनों के लिए ही प्रतिकूल स्थिति पैदा हो गयी है. केन्द्र सरकार की नीतियों के चलते, महाराष्ट्र तथा दूसरे राज्यों के कपास-उत्पादकों तथा कपड़ा मिल मजदूरों की भी हालत ऐसी ही बुरी है. कृत्रिम रेशों से प्रतियोगिता का, भारत के कपास-उत्पादकों के हितों पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है और किसान मांग कर रहे हैं कि उनके हितों की रक्षा की जाय. उस समय, जब अन्य मालों की कीमतें बढ़ रही हैं, कपास की कीमतें गिरने से और गारंटीशुदा कीमतें समर्थन मूल्य के स्तर पर आ जाने से, महाराष्ट्र के कपास-उत्पादकों के बीच भारी असंतोष पैदा हो गया है.

## मजदूरों पर बढ़ते हमले

जहां तक मजदूरों का सवाल है, नयी कपड़ा नीति से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है. सरकार कुछ अधिगृहीत बीमार मिलों को बंद करने की तैयारी कर रही है. मजदूरों से श्रम सहकारिताएं बनाकर इनमें से कुछ मिलें चलाने की पेशकश के जरिये उसने मजदूरों को बेबकूफ बनाने की कोशिश की है. ट्रेड यूनियनों ने, मौजूदा हालात में इस पेशकश की व्यर्थता को समझते हुए उसे उचित ही ठुकरा दिया है. सीटू को ही दूसरे उद्योगों में ऐसे ही तिकड़मों के बारे में मजदूरों को आगाह करना होगा. कुछ बंद फैक्टरियों में प्रबंधकों ने मजदूरों को मजदूरी की बकाया राशियां हिस्सा पूंजी में तब्दील करने के लिए कहा था. फैक्टरी दोबारा खुलने की यही सूरत बाकी थी. मजदूर इसके लिए राजी भी हो गये थे, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि मजदूरी से भी हाथ धोना पड़ा और संबंधित फैक्टरियां भी दोबारा नहीं खोली गयीं.

राष्ट्रीय कपड़ा मिलों के अधिकारीगण अब मजदूरों के साथ यही चाल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विश्व बैंक द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि अधिगृहीत मिलों को या तो वापस लौटा दिया जाय या बंद कर दिया जाय. एक सरकारी कमेटी ने औपचारिक रूप से सिफारिश भी कर दी है कि 8 बीमार मिलों को बंद कर दिया जाय. अभी पिछले ही दिनों जो रणनीति घोषित की गयी है, उसमें स्वैच्छिक रिटायरमेंट की एक आकर्षक योजना भी शामिल है, जिसके तहत सैकड़ों मजदूरों को बेकारी की दलदल में धकेल दिया जायगा. इसके अलावा, आधुनिकीकरण की, अत्याधुनिक करघों के आयात की मुहिम चलायी जायगी. कपड़ा उप-राज्यमंत्री ने कहा बताते हैं कि "राष्ट्रीय कपड़ा निगम के पास फालतू क्षमता है, जिसे छांटना होगा. तभी दीर्घावधि आर्थिक सक्षमता तथा लाभकारिता हासिल की जा सकती है." उस समय, जो आधा देश अधनंगा है और कपड़े का प्रति व्यक्ति खपत कुछ साल पहले के मुकाबले वास्तव में कम ही हुआ है, फालतू क्षमता की बात करना पागलपन नहीं तो और क्या है?

## महंगाई की बढ़ती मार

मजदूरों, बेकारों तथा देहाती जनता की तकलीफों को और बढ़ाने के लिए सभी चीजों की कीमतें और बढ़ रही हैं, जिससे मजदूरी में बढ़ोतरी, आय में बढ़ोतरी तथा पारिवारिक बजटों का मजाक बनकर रह गया है. और अगर रुपये की ताकत घटकर 9.7 पै. रह गयी है, तो इसके सिवा और उम्मीद ही क्या की जा सकती है. इसके अलावा, सूखे का असर मंडियों पर पड़ना अभी शुरू ही हो रहा है. लेकिन, कीमतें तेजी से बढ़ चली हैं और दुहरे अंकों में मुद्रास्फीति की ओर जा रही हैं. रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. अभी 24 अक्तूबर को समाप्त हुए सप्ताह में उपभोक्ताओं का थोक बाजार भाव, इसी साल मार्च के आखिर के इसी आंकड़े से 8.2 फीसद ऊपर पहुंच चुका था. पिछले सालों में बढ़ती रही कीमतों की पृष्ठभूमि में आयी इस साल की यह महंगाई, जनता पर अकथनीय तकलीफें डाल रही है. इसी अवधि में खाने-पकाने के तेलों की कीमतें 30.6 फीसद बढ़ी हैं, खाद्यान्नों की कीमतें 7.5 फीसद बढ़ी हैं और दूध की बनी चीजों की कीमतें 12.3 फीसद बढ़ी हैं.

स्वाभाविक रूप से, इस साल सितम्बर के महीने में औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 10.2 फीसद ऊपर पहुंच चुका था. 1986 के पहले छः महीनों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 8.5 फीसद बढ़ा था, जबकि 1987-88 के पहले छः महीनों में यही सूचकांक 8.8 फीसद ऊपर पहुंच गया है. इसकी सबसे बुरी मार पड़ रही है खेतमजदूरों तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर, जिन्हें इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ किसी भी तरह की सुरक्षा हासिल नहीं है. यही नहीं, महंगाई की भरपाई पर्याप्त न होने के चलते मजदूर तथा कर्मचारी भी छले जा रहे हैं. और, उन्हें इस भरपाई से और भी वंचित करने के लिए अब मजदूरों पर एक नयी मूल्य सूचकांक श्रृंखला थोपने की कोशिश की जा रही है, जो आंकड़ों की हेराफेरी के जरिये महंगाई भत्ता घटा देगी. सीटू तथा दूसरे ट्रेड यूनियन संगठनों ने श्रृंखला को ठुकरा दिया है.

बढ़ती कीमतें, महंगाई भत्ते में कमी तथा बढ़ती बेरोजगारी, ये वे हथियार हैं, जिन्हें बड़े पूंजीपतियों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के हित में अर्थव्यवस्था को 'स्थिर' करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है.

कामरेडों, इन्हीं कठिन परिस्थितियों के बीच हमारे देश का मजदूर वर्ग अपनी लड़ाई चला रहा है. और, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इन बहुत ही कठिन हालात में भी वह बड़ी बहादुरी के साथ यह लड़ाई चला रहा है. 1987 की जनवरी से जुलाई तक की अवधि में, 819 औद्योगिक विवादों में काम बंद

किया गया था. 10 लाख 23 हजार मजदूर इन विवादों में शामिल थे और इनमें 1 करोड़ 30 लाख 29 हजार श्रम दिनों की हानि हुई थी. 1986 में इसी अवधि (जनवरी-जुलाई) में 1,130 औद्योगिक विवाद उठे थे, जिनमें 9 लाख 57 हजार मजदूर शामिल हुए और 1 करोड़ 55 लाख 75 हजार श्रम दिन नष्ट हुए.

कामरेडों, हड़तालों का जिक्र करते हुए मैं, दिल्ली में **इंडियन एक्सप्रेस** के कर्मचारियों की हड़ताल की कुछ विशेषताओं का जिक्र किए बिना नहीं रह सकता हूं. बोनस के मुद्दे पर उत्पन्न विवाद के चलते हुई हड़ताल को जानबूझकर इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ हमले की साजिश के रूप में पेश किया गया, क्योंकि वह सरकार के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ कर रहा था. राजनीतिक पार्टियों के अनेक नेता इस अखबार के संपादक के मिथ्या प्रचार के शिकार हुए और हड़ताल की निंदा करने में शरीक हो गए. प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के दावेदारों को, दुष्प्रचार के जरिए मजदूरों की आवाज को दबाने में और पुलिस की मदद से हड़ताल तोड़ने की कार्रवाई में हिस्सा लेने में रत्ती भर झिझक नहीं हुई. यह बहुत ही शर्म की बात है कि इस अखबार के सपादक ने खुद, हड़ताल तोड़ने की कार्रवाई संगठित करने की कोशिश की थी, हांलांकि उठते-बैठते प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के नाम पर एक राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने भी, हड़ताल तोड़ने की कार्रवाई में मदद दी थी. लेकिन, जब उनकी यह कार्रवाई बेनकाब हो गई तो उन्होंने फौरन अपने पांव वापस खींच लिए और कहना शुरू कर दिया कि वे तो बस दर्शक बनकर गए थे, न कि हड़ताल तोड़ने की कार्रवाई के हिस्सेदार बनकर. पत्रकारों ने इन हड़तालतोड़क हथकंडों और कुछ पार्टियों के नेताओं की भी निंदा की है और ये पत्रकार बधाई के पात्र हैं. बहरहाल, इस घटना से साफ हो जाना चाहिए कि जो लोग प्रेस की स्वतंत्रता का दम भरते हैं, उनमें से अनेक ऐसे भी हैं. जो मजदूरों के संगठित होने तथा अपने हितों के लिए लड़ने के अधिकार को स्वीकार नहीं करते हैं. सीटू, जहां प्रेस की स्वतंत्रता का पक्ष लेती है, वहीं इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकती है कि अनेक अखबारों के मालिकों की असली दिलचस्पी अपने मुनाफों में है और वे अपने अखबारों को मुनाफे कमाने के उद्यमों के रूप में ही चलाते हैं. सीटू, मजदूरों को आगाह करती है कि उन्हें, जहां प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का विरोध करना चाहिए, वहीं यह भी याद रखना चाहिए कि इजारेदारों के हाथों में अखबारों तथा प्रेस का केंद्रीकरण अक्सर मिथ्या प्रचार तथा प्रेस के तंत्र को इजारेदारों के हितों की सेवा के लिए इस्तेमाल किये जाने की ओर ले जाता है.

कामरेडों, राजीव सरकार की नीतियों का प्रतिरोध आज कर्मचारियों तथा मजदूरों के सभी तबकों द्वारा किया जा रहा है. पिछले कुछ दिनों से, सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूर तथा उनके संगठन, अपनी मांगों के लिए एकजुट संघर्ष चलाते रहे है. हाल ही में वे, वांछित अंतरिम राहत, जितनी कि अफसरान को दी गई है, हासिल करने में सफल रहे हैं. यह एक बड़ी भारी जीत है, हांलांकि सरकार अब उन्हें इस राहत के एक हिस्से से वंचित करने की कोशिश कर रही है. पिछले कुछ अर्से में, सार्वजनिक क्षेत्र के अफसरान ने भी अपने अधिकारों की रक्षा तथा मांगों के हक में कहीं ज्यादा जागरूकता दिखाई है और कार्रवाइयां की हैं. यह ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए एक शुभ संकेत है. मजदूरों और अफसरान के संगठनों के बीच घनिष्ठ सहयोग होना चाहिए. दोनों को मिलकर, प्रबंधन के लिए अमरीकी अनुभव तथा प्रशिक्षण का आयात करने की सरकार की कोशिशों के खिलाफ लड़ना चाहिए.

सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के अलावा, राज्य सरकार कर्मचारियों समेत मजदूरों के दूसरे सभी हिस्से, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मैदान में हैं. राज्य सरकारों के आतंक तथा दाब-धौंस के बावजूद, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के राज्य-सरकार कर्मचारियों की बहादुरीपूर्ण हड़ताल से कर्मचारियों की एकता तथा एकजुटता की दृढ़ भावनाओं और उनके दृढ़ निश्चय का ही पता लगता है.

इतनी ही शानदार थी विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों की हड़ताल, इससे, अनेक विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के शिक्षकों की एकता की अभूतपूर्व लहर उठी. शिक्षकों की ऐसी देशव्यापी एकता इससे पहले कभी देखने में नहीं आई होगी. हड़ताल शानदार जीत की ओर बढ़ रही थी. लेकिन, गलत तथा अवसरवादी नेतृत्व के चलते, हड़ताल के साथ करीब-करीब धोखा ही हो गया. कालेज शिक्षकों, को विश्वविद्यालय के शिक्षकों से अलग करने का सरकार का रोल कामयाब हो गया. संगठन की व्यापक कार्यकारिणी से परामर्श किये बिना नेतृत्व ने सरकार के साथ सौदा कर लिया और इस तरह शिक्षकों की कतारों में फूट डाल दी. यह घटनाविकास सबके लिए एक सबक होना चाहिए, हड़ताल के दौरान यह जरूरी होता है कि सभी फैसले, तथा खासकर वार्ताओं से सम्बधित फैसले, जनतांत्रिक ढंग से किये जायें और फैसले लेने की शक्ति कुछ मुठ्ठी भर लोगों के हाथों में केंद्रित न हों.

कामरेडों, राजीव सरकार की आर्थिक नीति भारतीय अर्थव्यवस्था में घुस पैठ करने के बहुराष्ट्रीय निगमों को बढ़ावा दे रही है. अपने बम्बई सम्मेलन में, हमने इस पर गौर किया था कि किस प्रकार यह नीति, भारतीय उद्योगों पर बुरा असर डाल रही है और उसके चलते मजदूरों में रोजगार छिन रहा है. यह प्रक्रिया जारी है. बहरहाल गौर करने वाली बात यह है कि अपनी हेकड़ी तथा साजिशों में बहुराष्ट्रीय निगमों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. दवा उद्योग के बहुराष्ट्रीय निगम, अपनी हमदर्द सरकार द्वारा सारी रियायतें दिये जाने के बावजूद सारे कानूनी नियंत्रणों की अनदेखी कर रहे हैं, भारत दवा निर्माताओं की शिकायत हैं कि उन्हें, इन ताकतवर बहुराष्ट्रीय निगमों के खिलाफ कोई सुरक्षा हासिल नहीं हैं. ये ताकतवर

बहुराष्ट्रीय निगम भारत की जनता को नुकसानदेह दवाएं बेच रहे हैं. ऐसी-ऐसी दवाएं बेची जा रही है जो जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक करार देकर खुद उनके अपने देशों में प्रतिबंधित की जा चुकी है, और अब सरकार ने यूनियन कार्बाइड कंपनी की ताकत के आगे घुटने ही टेक दिए हैं. बताया जाता है कि उसने, हजारों गैसपीड़ितों के हितों के साथ विश्वासघात करके एक शर्मनाक सौदा करने का निश्चय कर लिया है. सरकार ने, भोपाल गैस विनाश लीला के लिए यूनियन कार्बाइड के खिलाफ 3 अरब डालर का दावा किया था. इस गैस कांड में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी, हजारों अपंग हुए थे और करीब दो लाख लोग गैस की चपेट में आए थे. उम्मीद की जाती थी कि मुआवजे के दावों पर सही ढंग से लड़ा जायगा और इसके साथ ही उन लोगों को दंड दिलाया जायगा, जिनकी मुजरिमाना लापरवाही से यह तबाही हुई थी. लेकिन अब, वजह क्या है, यह तो सरकार ही जानती होगी, घुटने टेक दिये है और सरकार 50-60 करोड़ डालर का मुआवजा ही स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई है और यह मुआवजा भी बीस साल में दिया जायगा. और किसी को दंडित किये जाने का तो खैर सवाल ही कहां उठता है. यह, एक ताकतवर बहुराष्ट्रीय कंपनी के सामने घुटने टेकने की शर्मनाक घटना है और सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए. बहरहाल, इससे यह भी पता लगता है कि किस प्रकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की तिकड़में, एक संप्रभुता संपन्न सरकार के मुकाबले भारी पड़ सकती है.

कामरेडों, पंजाब में पृथकतावादी ताकतों की चुनौती बहुत उग्र हो गई हैं और इस राज्य में जनतांत्रिक ताकतें अपने देश की एकता की रक्षा के लिए एक साहस भरी लड़ाई लड़ रही है. राजीव सरकार के अपराधपूर्ण अवसरवाद ने समस्या को और उलझा दिया है. उनकी सरकार ने, बरनाला मंत्रिमंडल को उस समय बर्खास्त कर दिया. जब वह खालिस्तानी आतंकवादियों तथा धार्मिक कठमुल्लापन के खिलाफ दृढ़तर रूख अपना रहे थे. इस रवैये को लेकर बरनाला तथा उनकी सरकार ने एक राजनीतिक भूमिका अदा की होती और पृथकवादियों को आम सिखों से अलग-थलग किया होता. लेकिन, हरियाणा में चुनाव जीतने के अवसरवादी समीकरणों की खातिर, बरनाला सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और इस प्रकार समस्या को और भी उलझा दिया गया. सीटू को, पंजाब के सीटू के अपने तथा अपनी ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्त्ताओं को बधाई देनी चाहिए, जिन्होंने मजदूरवर्ग की एकता की रक्षा की है और पृथकतावादियों के हमलों का मुकाबला कर रहे हैं, सीटू तथा अन्य संगठनों द्वारा दी गई कुर्बानियों का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं. इसमें कोई शक नहीं है कि सीटू की गतिविधियों के चलते, पंजाब का मजदूर वर्ग एक एकताकारी शक्ति के रूप में उभर कर ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है. सच तो यह है कि मजदूर वर्ग की ऐसी भूमिका के बिना, कोई भी नवस्वाधीन देश अपनी एकता की रक्षा कर ही नहीं सकता है. सीटू के नेतृत्व में मजदूर वर्ग इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी पूरी करना सीख रहा है. इसी तरह, पश्चिम बंगाल में मजदूर वर्ग, सांप्रदायिक जहर के फैलने के खिलाफ एक बड़ी बाधा तो बना ही हुआ है, पृथकतावादी 'गोरखालैंड' आंदोलन के खिलाफ देश की एकता की भी रक्षा कर रहा है. असम में मजदूर वर्ग ने पृथकतावादी आंदोलन के खिलाफ लड़ने में बहादुरीपूर्ण भूमिका अदा की और अनेक जानें कुर्बानी कीं. वह तमिलनाडु में, राष्ट्र-विरोधी अंध तमिलवादियों के खिलाफ लड़ रहा है, जो श्रीलंका की घटनाओं के सिलसिले में तमिल कट्टरता उभारने की कोशिश कर रहे हैं. इस तरह वहां मजदूर वर्ग, देश तथा अपने वर्ग की एकता की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है. केरल में, जैसाकि सभी जानते हैं, पिछला चुनाव सांप्रदायिकता का मुकाबला करने और सांप्रदायिक ताकतों के साथ कांग्रेस के अवसरवादी समझौतों को बेनकाब करने के आधार पर लड़े गए थे. यह मजदूर वर्ग के लिए एक अच्छी शुरूआत है, क्योंकि मजदूर वर्ग की एकता और विघटनकारी ताकतों के खिलाफ जनतांत्रिक ताकतों को एकजुट करने के लिए उसके संघर्ष के जरिए ही सांप्रदायिक, पृथकतावादी तथा क्षेत्र वादी ताकतों की बढ़ती चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है.

कामरेडों, साम्राज्यवादी साजिशों से देश की एकता की रक्षा करने के और कांग्रेस (आइ) सरकार की जनतंत्रविरोधी नीतियों के प्रतिरोध के इस संघर्ष में प. बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा की वामपंथी नेतृत्व वाली सरकारें, संघर्ष की अग्रिम चौकियां बनी हुई हैं. समूचे मजदूर वर्ग को उनकी इस भूमिका को पहचानना चाहिए और उन्हें अपना पूर्ण समर्थन देना चाहिए. कांग्रेस (आइ) पार्टी, यहां तक कि खुद प्रधान मंत्री द्वारा भी इन सरकारों के खिलाफ हर तरह का दुष्प्रचार किया जाता है और आर्थिक शक्ति तथा अधिकारों पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल करके इन सरकारों के लिए कठिनाइयां पैदा करने की कोशिशें की जाती हैं. कांग्रेस (आइ) पार्टी तथा उसकी सरकार, सूखा तथा बाढ़ राहत के उपायों को अपने चुनाव प्रचार के साधनों की नजर से देखती हैं और इसीलिए इन राज्यों को पर्याप्त सहायता देने से इनकार करती हैं. त्रिपुरा में ऋण मेले आयोजित कराये जा रहे हैं, जो मतदाताओं के वोट खरीदने की भौंडी कोशिश के सिवा और कुछ नहीं है, जिसका' जरूरतमंदों को मदद देने से कुछ भी लेना-देना नहीं है. इसके अलावा, त्रिपुरा में उनकी कोशिश यह भी है कि कानून तथा व्यवस्था की समस्या पैदा करके चुनावों को प्रभावित किया जाय. उनकी, कुख्यात टी एन वी के साथ मिलीभगत है, जो हत्याओं तथ आगजनी का रास्ता अपनाये हुए है और इस राज्य में लगातारा कानून तथा व्यवस्था की समस्या पैदा किए रहती है. कांग्रेस (आइ) जानती है कि वह, वैध तरीकों से तो त्रिपुरा में चुनाव जीत नहीं सकती है. इसीलिए वह, इन सारे अवैध हथकण्डों का सहारा ले रही है.

कामरेडों, हमारा देश सूखे तथा बाढ़ के गंभीर दौर से गुजर

रहा है. दसियों लाख देशवासी मुसीबत की चपेट में हैं और राहत के लिए पूरी तरह केन्द्र सरकार के प्रशासन पर ही निर्भर होने के लिए लाचार हैं, जो भ्रष्टाचार के लिए पहले ही कुख्यात हो चुकी है. यह स्वतःस्पष्ट है कि जिन लोगों के चेहरों पर प्रतिरक्षा सौदों में भ्रष्टाचार की कालिख लगी हुई है, उन पर सूखापीड़ित जनता को राहत पहुंचाने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है. राजनीतिक पार्टियों तथा जनसंगठनों को मांग करनी चाहिए कि राहत एजेंसियां राजनीतिक पार्टियों तथा जनसंगठनों की देखरेख में काम करें, ताकि पक्षपात, कुप्रबंधता तथा भ्रष्टाचार से मुक्त रहकर राहत का वितरण किया जा सके. सिर्फ इसी तरह से, ऊपर से चलनेवाली राहत का वास्तव में जनता तक पहुंचना सुनिश्चित किया जा सकता है.

कामरेडों, इस सिलसिले में हम सभी को दिल्ली मार्च आयोजित करने के वामपंथी पार्टियों के संगठनों के फैसले का स्वागत करना चाहिए. इस मार्च में किसानों की मांगें उठायी जायेंगी और काम के अधिकार तथा दूसरी मांगों पर जोर दिया जायगा. यह, सभी संगठनों को एकजुट करने का एक अभूतपूर्व प्रयास होगा. इस प्रयास में, फौरी मांगों के निपटारे और राजीव गांधी सरकार का इस्तीफा हासिल करने के लिए छात्र, युवा, महिलाएं, खेतमजदूर, मजदूर तथा किसान एकजुट होंगे. राजीव सरकार की प्रतिक्रियावादी अर्थिक नीतियों, भ्रष्टाचार घोटालों तथा अपनी पार्टी के क्षुद्र हितों के लिए सांप्रदायिक-प्रतिक्रियावादी ताकतों के साथ अवसरवादी समझौतों के चलते, राजीव गांधी के इस्तीफे की मांग को अब आम जनसमर्थन हासिल होता जा रहा है.

कांग्रेस (आई) के कुछ नेताओं की क्या हालत है, यह राजस्थान में उस समय उजागर हो गया, जब सतीकांड के खिलाफ न तो कांग्रस (आइ) सरकार ने दृढ़ रुख अपनाया और न कांग्रेस (आइ) नेताओं ने. पुराणपंथियों के सामने अपने आत्मसमर्पण को छिपाने के लिए उन्होंने अब सती के नामपर विधवा-दहन के लिए दंड का प्रावधान करते हुए एक अध्यादेश जारी किया है. यह, साधारण कानून करने में अपनी नपुंसकता को ढकने की ही कोशिश थी. यहां यह भी गौरतलब है कि लोकदल, जनता, भाजपा आदि लगभग सारी पूंजीवादी पार्टियां इस हत्यारी प्रथा के आगे झुक गयी हैं और उन्होंने इसे धर्म के नामपर उचित ठहराने की कोशिश की है और सरकार के हस्तक्षेप के खिलाफ शोर मचाया है. आजादी के चालीस साल बाद भी भारत में, एक जिंदा इंसान को खा जाने को छोड़कर, बाकी सारी सड़ी-गली कुप्रथाएं बनी हुई हैं. मजदूर वर्ग को यह समझाना चाहिए कि किस प्रकार जनता की स्वाधीनताओं तथा महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के अपने सारे दावों के बावजूद, सभी पूंजीवादी पार्टियां इस परीक्षा में खोटी साबित हुई हैं.

बहरहाल, राजीव गांधी की अवसरवादी, समझौतावादी नीति सिर्फ इतने पर ही नहीं रुक गयी है. पिछले कुछ समय से सुरक्षा उपकरणों, हल्के लड़ाकू विमान आदि के मामले में अमरीका से लगातार वार्ताएं चलती रही हैं, जबकि वह पाकिस्तान को नवीनतम हथियारों से लैस करने में लगा हुआ है. राजीव गांधी की हाल की अमरीका यात्रा से, प्रतिरक्षा के मामलों में अमरीकी मदद हासिल करने की यह नीति और मजबूत हुई है. यह एक खतरनाक रुझान है. इससे भारत, अमरीकी दबाव के सामने कमजोर हो जयेगा और सी आइ ए जैसी एजेंसियों को हमारे सुरक्षा राजों तक घुसपैठ करने का मौका मिल जायगा. इसके अलावा अब, भारतीय अफसरान को प्रशासन के क्षेत्र में अमरीकी विशेषज्ञता का प्रशिक्षण दिलाने और उनकी विशेषज्ञता से भारतीय अधिकारियों को लैस करने की एक और योजना भी चल रही है. हम, अच्छी तरह जानते हैं कि यह अमरीकी विशेषज्ञता, किस चीज की विशेषज्ञता है. सी आइ ए का उदाहरण बताता है कि यह विशेषज्ञता निर्वाचित पदाधिकारियों को धोखा देने और जनता को संदेह की नजर से देखने तथा उसे सरकार व मौजूदा व्यवस्था का दुश्मन मानने की ही विशेषज्ञता है.

यह घटनाविकास, नई आर्थिक नीति के चलते अब विश्व-बैंक द्वारा डाले जा रहे दबाव का ही स्वाभाविक परिणाम है. इस घटना विकास से, गुटनिरपेक्षता की सुपरीक्षित नीति के कमजोर होने का खतरा पैदा हो गया है. अमरीका खास तौर पर गुटनिरपेक्षता की इस नीति के खिलाफ, और उसमें भी विशेष रूप से सोवियत संघ तथा दूसरे समाजवादी देशों के साथ मैत्री की भारत की नीति के खिलाफ, अपना दबाव केंद्रित करता है उसे अच्छी तरह मालूम है कि समाजवादी देशों के साथ भारत की मैत्री और मैत्री व सहयोग की भारत सोवियत संधि, भारत की स्वतंत्रता व स्वाधीनता को मजबूत करती है और भारत को इसके लिए समर्थ बनाती है कि वह अमरीका की मदद से पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न खतरे तथा उसकी ब्लैकमेल का मुकाबला कर सकें.

राजीव के इस्तीफे की मांग, इनतमाम अवसरवादी तथा राष्ट्रविरोधी तिकड़मों का भी परिणाम है, जिनसे देश के बिखराव का ही खतरा पैदा हो रहा है.

लेकिन, विघटनकारी ताकतें भी सक्रिय हैं और राजीव सरकार के खिलाफ जनता के असंतोष का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है. भा ज पा तथा अन्य हिंदू पुनरुत्थानवादी संगठनों, मुस्लिम लीग तथा अन्य मुस्लिम सांप्रदायिक संगठनों और दूसरे सभी सांप्रदायिक संगठनों द्वारा आम जनतांत्रिक आंदोलन को भाई द्वारा भाई की हत्या की विनाशकारी दिशा में भटकाने की हर संभव कोशिश की जा रही है. साम्राज्यवाद के प्रतिक्रियावादी एजेंट, राजीव सरकार के खिलाफ जन-असंतोष का फायदा उठाकर और उसे सांप्रदायिक तथा जातिवादी रास्ते पर मोड़कर, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं. राजीव गांधी के खिलाफ जनतांत्रिक ताकतों की लड़ाई में, इन सांप्रदायिक प्रतिक्रियावादी ताकतों को भी अलग-थलग डालना चाहिए, जो देश के अस्थिर करने की भूमिका अदा कर रहे हैं और विखंडन तथा गुलाम बनाने की

(शेष पृष्ठ 18 पर)

# कांग्रेस(आइ) द्वारा ऋण मेले के नाम पर खून-खराबे की सीटू द्वारा भर्त्सना

सीटू के अध्यक्ष बी टी रणदिवे ने 29 अक्तूबर को निम्नलिखित बयान जारी किया है:—

त्रिपुरा में आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए केन्द्र सरकार तथा कांग्रेस (आइ) द्वारा अपनाई गई गैर-कानूनी हथकंडे की सी आई टी यू तीव्र भर्त्सना करती है. राज्य में दिसम्बर में चुनाव कराने की घोषणा की गई है. केन्द्र सरकार ने जानबूझकर ऋण मेले का आयोजन ही इसलिए किया है ताकि आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस (आइ) के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके. केन्द्र सरकार द्वारा ऋण मेलों का आयोजन एक सरासर पक्षपातपूर्ण हरकत थी, जिसके जरिये जरूरतमंद लोगों को ऋण देने के बजाय सिर्फ कांग्रेस (आइ) समर्थकों को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी. इसका पक्षपातपूर्ण और भ्रष्ट चरित्र उसी समय बेनकाब हो गया जब केबल कांग्रेस (आइ) विधायकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए आवेदनों को ही ग्रहण किया जा रहा था. 24 अक्तूबर को कांग्रेस (आइ) तथा उसके द्वारा जुटाए गए समाजविरोधियों ने वाम-मोर्चे के समर्थकों के खिलाफ हिंसा की मुहिम छेड़ दी जिससे 200 से भी अधिक लोग घायल हो गये. एक जगह सी पी आइ (एम) कार्यालय को तहस-नहस कर दिया गया. एक अन्य स्थान में आर एस पी के दफ्तर तथा उनके नेतृत्व पर हमला कर दिया गया और एक जगह राज्य के मंत्री श्री बादल चौधरी के घर पर हमला किया गया. इस ऋण मेले के मौके पर कांग्रेस(आइ) के लोगों ने जो संगठित हिंसा की थी उसका मक्सद उस समय स्पष्ट हो गया जब कांग्रेस (आइ) नेताओं ने त्रिपुरा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की. राष्ट्र-विरोधी टी एन बी हमलावारों से साठ-गांठ के कारण आगामी चुनाव में हारने की आशंका से कांग्रेस (आइ) नेतागण नाजायज ढंग से सत्ता हथियाने की आसान तरीके की कोशिश में लगे हैं. सी आइ टी यू कांग्रेस (आइ) की इन गतिविधियों की भर्त्सना करने तथा चुनाव के पहले ऋण मेलों के जरिए इन भ्रष्ट कार्रवाइयों को चलाने से बाज आने की मांग करने के लिए तमाम ट्रेड यूनियनों का आह्वान करती है.

---

(पृष्ठ 8 का शेष)

साम्राज्यवादी साजिश में मदद कर रहे हैं. कुछ पूंजीवादी विपक्षी पार्टियां, जो सिर्फ चुनावी खेल की भाषा में ही सोचती हैं, सांप्रदायिक पार्टियों से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं. ये पार्टियां, अल्पसंख्यकों को बेगाना बनाने में और जनता को विभाजित करने का साँप्रदायिक पार्टियों का ही खेल खेल रही हैं. जनता पार्टी, लोकदल तथा तेलगू देशम पार्टी के भी कुछ तत्व भी, इन्हीं पार्टियों के साथ संयुक्त राजनीतिक गतिविधियों की दिशा में सोच रहे हैं, जिससे जनतांत्रिक तथा साझा आंदोलन को नुकसान पहुंचाना तय है.

इसलिए मजदूर वर्ग को, राजीव गांधी के खिलाफ संघर्ष चलाने के लिए वामपंथी पार्टियों धर्मनिरपेक्ष विपक्षी पार्टियों और जनसंगठनों के बीच आपसी समझदारी बनानी चाहिए. इस समझदारी और सारी सांप्रदायिकताओं को अलग-थलग किये जाने से ही, कोई ऐसा नतीजा निकल सकता है, जो जनता तथा देश के हित में हो. मजदूर वर्ग तथा उसकी ट्रेड यूनियनों को भी अपने क्षेत्र में, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने में और धर्म तथा जाति के भेदों से उपर उठकर सभी मजदूरों की एकता कायम करने में, अपनी भूमिका अदा करनी होगी. ट्रेड-यूनियनों को यह सुनिश्चित करने के लिए अलग से प्रयास करने चाहिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के मजदूर तथा उत्पीड़ित जातियों के मजदूर ट्रेड यूनियनों में विशेष रूप से भर्ती किए जायें और इन संगठनों द्वारा उनकी विशेष समस्याएं उठाई जायें, ताकि वे ट्रेड यूनियनों को, आर्थिक मांगों के लिए मैनेजमेंट के खिलाफ लड़ने के साझा संगठन के रूप में ही नहीं, बल्कि सामंती तथा सांप्रदायिक बीमारियों के खिलाफ संघर्ष के भी साझा संगठन के रूप में देखें. सांप्रदायिकता, मजदूर वर्ग की वर्गीय एकता को तोड़ रही है और अगर मजदूर इस एकता की रक्षा नहीं कर पाता है, तो वह देश की एकता की भी रक्षा नहीं कर सकेगा.

ट्रेड यूनियन आंदोलन आज बहुत बड़ा हो चुका है और वह अन्य जनसंगठनों की मदद से, खासकर तीन वाम मोर्चा सरकारों तथा वाम-जनतांत्रिक ताकतों की मदद से राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ संघर्ष को नेतृत्व प्रदान करने और साम्राज्यवाद की अस्थिरता की साजिश को नाकाम करने तथा जनता को विभाजित करने के सांप्रदायिक, प्रतिक्रियावादियों के खेल को शिकस्त देने की स्थिति में है. आज जब तीन वाम मोर्चा सरकारें जनतांत्रिक संघर्ष की अग्रिम चौकियों के रूप में मौजूद हैं, मजदूर वर्ग की एकजुटता ताकत देश में जनतंत्र की रक्षा करने और तमाम जनतंत्रविरोधी ताकतों को शिकस्त देने की अपनी भूमिका पूरी करने में समर्थ होगा. मजदूर वर्ग को समझना चाहिए कि तीन वाम मोर्चा सरकारों के रूप में उसके पास तीन अगुआ दस्ते मौजूद हैं, जो उसे अपनी एकता का निर्माण करने में, ट्रेड यूनियन आंदोलन की अपनी ताकत का निर्माण करने में और देश के सारे दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में मदद देते हैं. इन तीन सरकारों की उपलब्धियों का मजदूरों तथा जनता के सभी तबकों के बीच पूरा-पूरा प्रचार किया जाना चाहिए, ताकि उनकी नीतियां तथा गतिविधियों के जरिए जनतांत्रिक ताकतें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकजुट कर सकें और प्रतिक्रियावादी ताकतों को अलग-थलग कर सकें.